

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक /5 जुलाई, 2016

विषय:— एल०टी० इण्डस्ट्री श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्ब भुगतान अधिकार में छूट प्रदान करने की योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में एल०टी० इण्डस्ट्री श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के विरुद्ध लम्बित विद्युत देयों की वसूली के उद्देश्य से इन उपभोक्ताओं को बिलम्ब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल०टी० इण्डस्ट्री श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्ब भुगतान अधिकार में छूट प्रदान करने की योजना निम्नानुसार लागू की जाती है:—

- (1) इस श्रेणी से लगभग रू० 3.00 करोड़ प्राप्त होंगे एवं रू० 1.50 करोड़ बिलम्ब भुगतान अधिभार के माफ किए जायेंगे।
- (2) बिलम्ब भुगतान अधिभार की माफ की जाने वाली राशि का समायोजन मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित "Provision for Bad and Doubtful Debts" से कर लिया जायेगा।
- (3) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा उनके बिल की मूल धनराशि का भुगतान किया जायेगा, जिससे उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के राजस्व में वृद्धि होगी एवं इस धनराशि का उपयोग कारपोरेशन द्वारा अपने संसाधनों की वृद्धि में किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।


संख्या—876 / I(2) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

...2

3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बाडोनी)
उप सचिव।
√